

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1587
जिसका उत्तर 4 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
13अग्रहायण, 1946 (शक)

जनजातीय युवाओं की डिजिटल साक्षरता दर

1587.श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जनजातीय युवाओं में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी में साक्षरता दर अन्य की तुलना में सबसे कम है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार विशेष रूप से त्रिपुरा में जनजातीय आबादी पर विशेष ध्यान देने के साथ डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 10.43 करोड़ है, जो कुल आबादी का 8.6% और ग्रामीण आबादी का 11.3% है। एमईआईटीवाई की प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडिशा) योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत, 31 मार्च, 2024 तक देश भर में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जबकि लक्ष्य 6 करोड़ का था। यह योजना समाप्त हो चुकी है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अपने 79 वें दौर (जुलाई, 2022 से जून, 2023) में 'व्यापक वार्षिक मांज्यूलर सर्वेक्षण' (सीएएमएस) आयोजित किया और उनकी रिपोर्ट के आंकड़ों ने इंटरनेट पहुंच, स्मार्टफोन के उपयोग जैसे डिजिटल जुड़ाव के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रवृत्तियों का संकेत दिया।

त्रिपुरा राज्य में पीएमजीडिशा योजना के तहत कुल 82,301 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नामांकित किया गया और 65,174 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।
